Regarding construction of North Koel Irrigation Project-laid

श्री सुशील कुमार सिंह **(**औरंगाबाद**):** बिहार-झारखंड दो-दो राज्यों के लगभग 25 लाख किसानों की 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करने वाली अंतरर्राज्यीय उत्तर कोयल परियोजना का कार्यारंभ 1975 में हुआ । अभी तक हज़ारों करोड़ रुपये से अधिक ख़र्च करने के बावजूद भी दोनों राज्यों के तीन ज़िलों पलामू, औरंगाबाद और गया के किसान एक निश्चित सिंचाई सुविधा से वंचित हैं । जबकि शेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु 2017 में केंद्रीय मंत्री परिषद ने 1622 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी । 5 जनवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शेष कार्यों को पूरा करने हेतु शिलान्यास किया गया और कार्यावधि 30 महीने निर्धारित की गई । समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने की वजह से निर्माण लागत में वृद्धि के कारण पुनः अक्टूबर 2023 में केंद्रीय मंत्री परिषद ने 2436 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की । जिसके तहत डूब क्षेत्र के किसानों को पुनः मुआवज़ा, मंडल डैम में लोहे का फाटक, मोहम्मदगंज बराज और दाएँ-बाएँ नहरों के जीर्णोद्धार का कार्य होना है । इन सभी कार्यों विशेषकर मुआवज़ा भुगतान करने में झारखंड सरकार का सहयोग अपेक्षित है । मेरी भारत सरकार से माँग है कि लाखों किसानों के हित में 48 वर्षों से लंबित परियोजना के मंडल डैम में अविलम्ब लोहे का गेट लगाया जाए ।